महात्मा की विरासत : खादी की बिक्री में इजाफा

विशेष लेख
खादी

*नीरज बाजपेयी

प्राकृतिक चमक और स्थूल बुनावट के लिए लोकप्रिय, खादी के धागे हाल ही में कई तरह से सजीव तंतु सिद्ध हुए हैं, क्योंकि खादी में गतिशीलता आयी है, इसकी बिक्री में बढ़ोतरी से प्रौद्योगिकी उन्नयन, बुनकरों के लिए बेहतर भुगतान और कार्य वातावरण तथा सूत के दामों पर नियंत्र रखने जैसी मांगे की जा रही हैं। चरखे के घूमते चक्र के साथ खादी को लेकर बहस बढ़ती जा रही है, जिसकी शुरुआत मुख्य रूप से शीर्ष स्तर पर प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से खादी को प्रोत्साहित करने की बात कही थी। तब से लेकर एक वर्ष की अवधि में खादी की बिक्री लगभग दुगुनी हो गई और ज्यादा से ज्यादा लोग अब खादी की वस्तुएं खरीदने लगे हैं। सरकार के दावों से भिन्न राय रखने वाले कुछ लोग अब यह कहने लगे हैं कि बिक्री का हौआ खड़ा करके प्रचार किया जा रहा है। खादी एवं ग्राम उद्योग के वरिष्ठ अधिकारी देशभर में इसकी खरीद-फरोख्त पर निगरानी रख रहे हैं। खातों का रखरखाव करने वाले यह जोर देकर कह रहे हैं कि पहले की तुलना में खरीद अवश्य बढ़ी है।

अपने लोकप्रिय कार्यक्रम 'मन की बात' में पिछले वर्ष श्री मोदी ने लोगों का आह्वान किया था कि वे खादी का कम से कम एक वस्त्र अवश्य खरीदें। हाल ही में उन्होंने याद दिलाया किया कि उनकी अपील के फलस्वरूप खादी की बिक्री बढ़कर दुगुनी हो गई। उन्होंने कहा कि इसे एक अद्भुत अनुभव बताते हुए उन्होंने कहा यह उपलब्धि विज्ञापनों के जरिए हासिल नहीं की गई, बल्कि व्यापक जनशक्ति का परिणाम रही। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे लोगों को पूरी तरह "खद्दरधारी" बनने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि दीपावली के अवसर पर खादी की कुछ वस्तुएं खरीदने का आग्रह कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि खादी पर छूट कार्यक्रम का लाभ भी उठाया जा सकता है, जो 2 अक्टूबर से प्रारंभ होती है और लोगों को हथकरघों को संरक्षण प्रदान करना चाहिए। इस वर्ष 2 अक्टूबर को खादी के प्रति लोगों का जुनून स्पष्ट तौर पर महसूस किया गया, जब मात्र एक ही दिन में देशभर में खादी के विक्रय केन्द्रों पर 20 करोड़ रुपये की बिक्री हुई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सम्मान में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के 48 कार्यालय खुले रहे और 7050 विक्रय केन्द्रों ने भारी सेल की। नई दिल्ली में रीगल बिल्डिंग स्थित खादी भंडार की सेल गांधी जयंती के दिन 80 लाख रुपये पर पहुंच गई।

इससे खादी की बिक्री और नतीजतन उसके उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री कलराज मिश्र ने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के बाद खादी की बिक्री में अक्टूबर 2014 से मार्च 2015 की अवधि में 17.55% का इजाफा हुआ। पिछले वर्ष की इसी अवधि से तुलना करें तो यह वृद्धि तीन गुणा अधिक थी। प्रधानमंत्री की अपील के बाद उत्पादन में अक्टूबर 2014 से मार्च 2015 की अवधि में 31.1% का इजाफा हुआ, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि से तुलना में लगभग 6 गुणा अधिक था। 2014-15 में, खादी उत्पादन 880 करोड़ रुपये मूल्य का था, जो 2013-14 की तुलना में 8.5% अधिक था।

केवीआईसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और आयुक्त, अरुण कुमार झा के अनुसार प्रमुख विभागीय बिक्री केन्द्र, खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली, की बिक्री में प्रधानमंत्री के रेडियो कार्यक्रम के बाद प्रथम पखवाड़े में ही करीब 125 प्रतिशत वृद्धि हुई। अक्टूबर 2014 से मार्च 2015 की अवधि में बिक्री में कुल वृद्धि मूल्य के संदर्भ में करीब 68 प्रतिशत हुई। खादी की बिक्री जो अक्टूबर 2013 से मार्च 2014 की अवधि में 5.47 करोड़ रुपये की थी, वह अक्टूबर 2014 से मार्च 2015 की अवधि में बढ़ कर 9.19 करोड़ रुपये हो गई। उनके अनुसार कनॉट प्लेस स्थित

खादी ग्रामोद्योग भवन में रेडीमेड वस्तुओं की बिक्री में करीब 86 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज हुई। खादी की अखिल भारतीय बिक्री जो अक्टूबर 2013 से मार्च 2014 की अवधि में 581 करोड़ रुपये की थी, वह अक्टूबर 2014 से मार्च 2015 की अवधि में बढ़ कर 750 करोड़ रुपये हो गई। केवल मार्च तक यह वृद्धि 31 प्रतिशत दर्ज हुई।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने बाज़ार विकास सहायता कार्यक्रम (एमडीए) शुरू किया, जिसमें खादी संस्थानों को इस बात की पूरी छूट दी गई कि वे अपनी उत्पादन और बिक्री गतिविधियों का संचालन ऐसे उत्कृष्ट तरीके से करें, जो वे उचित समझते हों।

बाज़ार विकास सहायता कार्यक्रम (एमडीए) से खादी कार्यक्रम को अपेक्षित बल मिला। 2014-15 के दौरान सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत खादी संस्थानों की सहायता के लिए 324.64 करोड़ रुपये प्रदान किए, जो पिछले वर्ष, यानी 2013-14 में दी गई 239.17 करोड़ रुपये की सहायता की तुलना में 86 प्रतिशत अधिक थे।

अधिकारियों के अनुसार महात्मा गांधी की गौरवशाली विरासत और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के सक्षम उपकरण के रूप में खादी ‘‘नीतिपरक और राष्ट्रीय’’ होने के साथ-साथ प्राकृतिक, हस्त निर्मित, पर्यावरण अनुकूल, जैव-अपघटीय और शोषण-मुक्त रेशा है। यह हाथ से बना ऐसा वस्त्र है, जिसमें केवल हाथ से कते हुए धागे का इस्तेमाल होता है। इसके उत्पादन में प्राकृतिक रेशों यानी कपास, ऊन और रेशम का इस्तेमाल किया जाता है। खादी की पहचान धागे में घुमाव की दिशा से की जाती है। खादी के धागे के घुमाव की दिशा अंग्रेजी अक्षर "एस" की तरह होती है। सामान्यः इसे बायां घुमाव अथवा घड़ी की सुइयों के विपरीत घुमाव कहा जाता है।

वर्तमान में देश में 1.42 लाख बुनकर और 8.62 लाख कताई करने वाले कारीगर हैं। इनमें अधिकतर की मांग है कि उनके कौशल के बदले आकर्षक लाभ मिलने चाहिए। एक अनुमान के अनुसार 9.60 लाख चरखों और 1.51 लाख करघों पर खादी की कताई की जाती है। दिल्ली विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर, विनोद त्यागी, जो अभी भी चरखे पर खादी बुनते हैं और इस कार्य में अपनी माता जी का साथ देते हैं, का कहना है कि खादी वस्तुएं "अत्यंत महंगी" हो गयी हैं और एक धोती का दाम "महिलाओं' की डीसेंट सूती धोती" के समान हो गया है।

चेन्नई स्थित एतिराज गोपाल, जो खादी के प्रबल समर्थक हैं, का कहना है कि खादी को अधिक आयामों वाली और बेहतर गुणवत्ता युक्त बनाने की आवश्यकता है ताकि एक बार समुचित रूप में तैयार करने के बाद इसके वस्त्रों की क्रीज कई दिनों तक बनी रहे। पेशे से वकील, श्री गोपाल, का कहना है कि देशभर की यात्रा करते समय उन्होंने यह महसूस किया है कि केवीआईसी को परंपरागत खाद्य वस्तुओं- कार्बनिक खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए बाजारों और होटलों में गहरी पैठ कायम करनी चाहिए क्योंकि इनकी बिक्री की व्यापक संभावनाएं हैं। इससे देश के राष्ट्रीय भोजन को संरक्षित किया जा सकता है, जिसमें औषधीय और स्वाद संबंधी विशेषताएं हैं। कई लोग खादी की गुणवत्ता की कड़ी जांच की मांग करते हैं ताकि खादी और केवीआईसी की अन्य वस्तुओं में नकली सामान का प्रवेश रोका जा सके। खादी के दाम और गुणवत्ता, दोनों के बारे में केवीआईसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कहना है कि वह केवल गुणवत्तापूर्ण उत्पादों को खादी ब्रैंड देने के लिए कड़े नियम लागू कर रहे हैं और "बिक्री की मात्रा बढ़ने पर, दाम स्वयं ही नीचे आ जाएंगे।"

खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग (केवीआईसी) की स्थापना 1957 में की गयी थी। इसका उद्देश्य आजादी के प्रतीक वस्त्र, खादी की बेजोड़ विशेषताओं को उजागर करना था ताकि ग्रामीण कारीगरों का आर्थिक उत्थान किया जा सके और खादी कार्यक्रम को देश की योजना प्रक्रिया के साथ एकीकृत किया जा सके। केवीआईसी को रोजगार प्रदान करने जैसे सामाजिक दायित्व और बिक्री योग्य वस्तुएं उत्पादित करने के आर्थिक दायित्व सौंपे गए। अनेक लोगों का कहना है कि जब केवीआईसी की स्थापना की गयी थी तो इसका मुख्य लक्ष्य ग्राम और खादी उद्योग का विकास करना था। परन्तु विकास का वाहक बनने की बजाए यह इंजीनियरों, बाजार विशेषज्ञों, डिजाइनरों और गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं का एक नियामक निकाय बनकर रह गया।

अधिकारियों के अनुसार 2014-15 में केवीआई क्षेत्र के अंतर्गत खादी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में 2,223 संस्थानों को शामिल किया गया। वर्ष के दौरान खादी का उत्पादन 879.98 करोड़ रुपये मूल्य का था और इस क्षेत्र में 11.06 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त था। मात्रात्मक संदर्भ में खादी उत्पादन करीब 951.9 लाख वर्गमीटर वस्त्र का रहा, जो देश के कुल वस्त्र उत्पादन का मात्र 0.15 प्रतिशत है। यदि खादी की तुलना देश के परंपरागत वस्त्र क्षेत्र यानी ऊन और रेशम क्षेत्र से करें तो खादी का योगदान 11 प्रतिशत से अधिक रहा है।

2014-15 में खादी उत्पादन की बात करें, तो कुल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 25.23 प्रतिशत रहा, जिसका मूल्य 222.01 करोड़ रुपये था। इसकी तुलना में अन्य राज्यों का योगदान इस प्रकार रहाः तमिलनाडु-10.72 प्रतिशत और मूल्य रूपये 94.33 करोड़, पश्चिम बंगाल-13.27 प्रतिशत और मूल्य रूपये 116.74 करोड़, हरियाणा-9.67 प्रतिशत और मूल्य रूपये 85.15 करोड़, राजस्थान-5.82 प्रतिशत और मूल्य 51.18 करोड़। खादी के उत्पादन के आंकड़ों में कपास, ऊन और रेशम शामिल है।

अधिकारियों के अनुसार खादी से संबंधित कार्यक्रमों में केवीआईसी समर्थित केन्द्रीय क्षेत्र के विभिन्न खादी कार्यक्रम शामिल है - बाजार विकास सहायता (एमडीए), खादी एवं पोलीवस्त्र के लिए ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आईएसईसी) कार्यक्रम, परंपरागत उद्योगों के जीर्णोद्धार के लिए वित्त पोषण कार्यक्रम (स्फूर्ति), खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम (केआरडीपी), खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड कार्यक्रम, आम आदमी बीमा योजना, खादी कारीगर जनश्री बीमा योजना (जेबीवाई), कमजोर खादी संस्थानों का ढांचा सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम और कच्चा माल प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत विपणन ढांचे के लिए सहायता कार्यक्रम। नए मॉडल चरखा कार्यक्रम के लिए गुणवत्तापूर्ण कच्चा माल सुनिश्चित करने के लिए केवीआईसी ने 6 केन्द्रीय सिल्वर प्लांटों की स्थापना कूत्तुर (केरल), चित्रदुर्ग (कर्नाटक), सिहोर (मध्यप्रदेश), एटा और रायबरेली (उत्तर प्रदेश) और हाज़ीपुर (बिहार) में की है।

इन प्लांटों की कुल संस्थापित क्षमता 4100 टन प्रतिवर्ष है और 2014-15 में इनका उत्पादन करीब 2700 टन रहा। केवीआईसी ने इन प्लांटों की स्थापना पिछली सदी में 80 के दशक के उत्तरार्ध और 90 के दशक के शुरू में की थी। इन पर औसत निवेश करीब 6 करोड़ रूपये किया गया था। मौजूदा संस्थापित क्षमता के एक नए संयंत्र की स्थापना के रूप में वर्तमान में करीब 12.00 करोड़ रूपये के निवेश की योजना है। परन्तु, इन संयंत्रों को आर्थिक पैमाने की दृष्टि से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि एक सीएसपी की संस्थापित क्षमता प्रति प्लांट प्रति वर्ष 2000 टन होनी चाहिए। ब्रैंड उत्पादन के लिए विपणन उपायों के तहत केवीआईसी ने तीन ब्रैंड "खादी", "सर्वोदय" और "देसी आहार" विकसित किए हैं। इनमें खादी ब्रैंड प्रीमियम और निर्यात उन्मुखी केवीआई उत्पादों को दर्शाता है, "सर्वोदय" घरेलू बाजार खंडों में तीव्र गतिशील उपभोक्ताओं की जरूरतें पूरी करता हैं और "देसी आहार" कार्बनिक खाद्य उत्पादों के विपणन से संबद्ध है। विशेषज्ञों का कहना है कि खादी का एकल ब्रैंड होना चाहिए और तीन ब्रैंडों की बजाय मात्र एक ब्रैंड को प्रोत्साहित किया जा चाहिए।

महात्मा गांधी ने खादी को प्रोत्साहन देने के बारे में कहा था कि "स्वराज की तरह, खादी भी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हमारा यह जीवन पर्यन्त दायित्व है कि हम केवल उसी का प्रयोग करें। जो व्यक्ति इस दायित्व को पूरा नहीं करता उसे स्वराज का अर्थ मालूम नहीं है, जब तक खादी को हम एक सार्वभौम मुद्रा की तरह नहीं बनाएंगे तब तक हम यह दावा नहीं कर सकते कि हमें स्वराज के अर्थ की समझ है।" तेज़ी से बदलती परिस्थितियों और बड़ी आकांक्षाओं के बीच, खादी क्षेत्र को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जैसे सुनिश्चित गुणवत्ता के साथ मूल्य संवर्धन की प्रक्रिया के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन का सीमित होना, संस्थानों/इकाइयों के उत्पादन ढांचे की सहायता और उसे मज़बूत बनाने का कोई कार्यक्रम न होना, दीर्घावधि के लिए डिजाइन विकास के बारे में कोई कार्यक्रम न होना, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और बड़ी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा, अपर्याप्त तकनीकी कार्मिक, विज्ञापन और प्रोत्साहन अभियान के लिए संसाधानों का अभाव और बड़े भंडारों की स्थापना के लिए सक्षम कार्यक्रमों का अभाव।

विशेषज्ञों के अनुसार खादी के लिए विकासात्मक सहायता की आवश्यकता है। तत्संबंधी प्रस्तावों में अन्य बातों के अलावा प्रौद्योगिकी संबंधी औजारों एवं उपकरणों के उन्नयन के लिए तकनीकी कार्मिकों की भर्ती और सुनिश्चित गुणवत्ता के साथ मूल्य संवर्धन की प्रक्रिया को अनुकूलतम बनाने के लिए अन्य उत्पादक ढांचे का निर्माण, फैशनेबुल उत्पादों के डिजाइन एवं विकास में नवीनता के लिए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थानों से जाने-माने डिजाइनरों की भर्ती जैसे उपाय शामिल हैं। उनका कहना है कि युवा पीढ़ी पर ध्यान केंद्रित करते हुए विशिष्ट वस्तुओं के विकास की तत्काल आवश्यकता है। इससे अधिक मांग वाली और अधिक लाभ देने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए उच्च स्तरीय फैशन डिजाइनरों को आकर्षित किया जा सकेगा। खादी क्षेत्र को व्यापार में प्रतिस्पर्धा करने योग्य बनाने के लिए सूचना, ज्ञान और विशेषज्ञता सहित सभी अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए इस क्षेत्र के पूर्ण जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। इसके लिए खादी क्षेत्र में उपलब्ध विपणन नेटवर्क को मज़बूत बनाना होगा। विशेषज्ञों के अनुसार इस क्षेत्र को ऐसे जाने-माने व्यक्तियों और निकायों को प्रोत्साहन उपायों में शामिल करना होगा, जिनकी खादी में रूचि हो और उन्हें प्रेरित करना होगा कि वे क्षेत्रों, उत्पादों, परंपरागत उद्योग समूहों को अपनाएं और खादी एवं ग्राम उद्योग उत्पादों के विपणन और उन्हें लोकप्रिय बनाने की व्यवस्था करें। विशेषज्ञयों की यह भी मांग है कि विदेश में चुने हुए शहरों में डिजाइनर भंडार खोले जाएं ताकि वहां खादी एवं ग्राम उद्योग उत्पादों को स्थायी आधार पर प्रदर्शित और प्रोत्साहित किया जा सके। वे व्यावसायिक दृष्टि से संचालित संस्थान की स्थापना के भी पक्ष में हैं जो इस क्षेत्र द्वारा निर्मित उत्पादों की पूर्ण विपणन क्षमता का लाभ उठा सके और इन उत्पादों की मांग पैदा कर सके।

(नीरज बाजपेयी यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इण्डिया (यूएनआई) में संयुक्त संपादक हैं। लेख में व्यक्त विचार उनके व्यक्तिगत विचार है।)

(पीआईबी फीचर)